

दृष्टिकोण

कला, मानविकी एवं वाणिज्य की मानक शोध पत्रिका

संपादक

डॉ. अश्विनी महाजन

रीडर, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

दृष्टिकोण प्रकाशन

वर्ष : 11 अंक : 4 □ जुलाई-अगस्त, 2019

दृष्टिकोण

संपादक मंडल

प्रो. लॉरेंस ओएडिजी
वेगेनिंग विश्वविद्यालय, नीदरलैंड
डॉ. मार्टिन ग्रिन्डले
नॉटिंगम विश्वविद्यालय, लंदन
डॉ. अरुण अग्रवाल
ट्रेन्ट विश्वविद्यालय, पीटरबोरो, ओन्टारियो
डॉ. दया शंकर तिवारी
राजधानी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय
डॉ. आनंद प्रकाश तिवारी
काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, वाराणसी
डॉ. सुरज नन्दन प्रसाद
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया
डॉ. प्रकाश सिन्हा
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

डॉ. दीपक त्यागी
दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर
डॉ. सी.पी. शर्मा
विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग
डॉ. अरुण कुमार
रांची विश्वविद्यालय, रांची
डॉ. महेश कुमार सिंह
सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय, दुमका
डॉ. पूनम सिंह
बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर
डॉ. एस. के. सिंह
पटना विश्वविद्यालय, पटना
डॉ. अनिल कुमार सिंह
जे.पी. विश्वविद्यालय, छपरा
डॉ. मिथिलेश्वर
वीर कुंअर सिंह विश्वविद्यालय, आरा

संपादकीय सम्पर्क:

448, पॉकेट-5, मयूर विहार, फेज-I, दिल्ली-110091

फोन : 011-22753916, 40564514, 35522994 Mobile: 9710050610, 9810050610

e-mail : editorialindia@yahoo.com; editorialindia@gmail.com; delhijournals@gmail.com

Website : www.ugc-care-drishitikon.com

©Editorial India

Editorial India is a content development unit of Permanence Education Services (P) Ltd.

ISSN 0975-119X

नोट: पत्रिका में प्रकाशित लेखकों के विचार अपने हैं। उसके लिए पत्रिका/संपादक/संपादक मंडल को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। पत्रिका से सम्बंधित किसी भी विवाद के निपटारे के लिए न्याय क्षेत्र दिल्ली होगा।

सम्पादकीय

अर्थव्यवस्था धीमी जरूर पर बेहतर

पिछले कुछ समय से अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं समेत कई संस्थाओं एवं व्यक्तियों द्वारा अर्थव्यवस्था में सुस्ती और धीमेपन पर चिंता व्यक्त की जा रही है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था की विकास दर में कमी के कारण चिंता होना स्वाभाविक ही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह अर्थव्यवस्था में मंदी की ओर इंगित करती है या फिर यह धीमापन अल्पकालिक ही है। इस संदर्भ में दो प्रकार के परस्पर विरोधी बयान आते रहे हैं। एक ओर लोगों का कहना है कि अर्थव्यवस्था में मंदी आ गई है या आने का शुरुआती संकेत है। वे इस संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थाओं जैसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ), विश्व बैंक और मूडीज सरीखी रेटिंग एजेंसियों का हवाला देते हैं।

गौरतलब है कि आइएमएफ द्वारा 2019-20 में विकास की संभावनाओं को घटाकर 6.1 प्रतिशत कर दिया है। वहीं विश्व बैंक ने भी इसे 6.0 प्रतिशत पर आंका है। उधर मूडीज नाम की अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी ने भारत की साख रेटिंग को 'स्थिर' से घटाकर 'नकारात्मक' कर दिया है और उसके बाद एजेंसी ने वर्ष 2019 के लिए आर्थिक विकास की संभावनाओं को अपने पूर्व के 5.8 प्रतिशत के लक्ष्य को घटाकर 5.6 प्रतिशत कर दिया है। दूसरी ओर, सरकार समेत कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि आर्थिक विकास में मात्र कुछ धीमापन आया है पर मंदी की कोई आशंका नहीं है। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत में ही वित्तमंत्री ने अपने बयान में कहा कि हाल में आर्थिक विकास में आए धीमेपन के बावजूद आइएमएफ के अक्टूबर 2019 के वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण में भारत को जी-20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बताया है। इस बीच, मुद्रास्फीति जो लंबे समय से काफी कम चल रही थी, सितंबर 2019 के 3.99 फीसदी से बढ़कर अक्टूबर 2019 में 4.62 फीसदी हो गई। यह वृद्धि खाद्य पदार्थों की मुद्रास्फीति के कारण हुई। गौरतलब है कि अक्टूबर में खाद्य पदार्थों में खुदरा मुद्रास्फीति 7.89 फीसदी दर्ज की गई, जो पिछले माह 5.1 फीसदी ही थी।

मुद्रास्फीति में आए इस उछाल से प्रभावित होकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बयान दिया है कि अर्थव्यवस्था 'स्टंगफ्लेशन' यानी 'मुद्रास्फीति' के साथ आर्थिक ठहराव की स्थिति में प्रवेश कर सकती है। गौरतलब है कि 'मुद्रास्फीति' हालांकि आम भाषा में कीमतों में वृद्धि को कहते हैं लेकिन आर्थिक सिद्धांतों के अनुसार कीमतों में हर वृद्धि को मुद्रास्फीति नहीं कहते। किसी एक माह या किसी एक वर्ष या दो-तीन वर्षों तक की कीमत वृद्धि को भी मुद्रास्फीति नहीं कहा जाता। कीमत वृद्धि को मुद्रास्फीति कहने के लिए उसे लंबे समय तक भारी वृद्धि होना पड़ेगा। गौरतलब है कि मोदी सरकार के आने के बाद कीमतों में वृद्धि न केवल घटती गई, एक समय तो यह तीन प्रतिशत से भी कम हो गई थी। एक बयान के अनुसार कीमतों में लगातार कम वृद्धि के कारण पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह चिंता व्यक्त कर रहे थे कि इसके कारण देश में आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आ रही है। उनके इस बयान से काफी बड़ी संख्या में अर्थशास्त्री, बैंकर और अन्य जानकार सहमत थे कि आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए मुद्रास्फीति में होने वाली लगातार गिरावट को रोकना चाहिए। आज जब मुद्रास्फीति मात्रा एक-दो माह में बढ़ी है, इसे 'स्टेगफ्लेशन' कहना राजनीति से प्रेरित ही माना जाएगा। वो भी तब, जबकि एक माह पहले ही मनमोहन सिंह मुद्रास्फीति में लगातार कमी से चिंताग्रस्त थे और मुद्रास्फीति में वृद्धि को आर्थिक गतिविधियों में उठाव के लिए जरूरी मान रहे थे। वास्तव में समझना होगा कि लगातार कम होती कीमतें, रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में अपेक्षित कमी न किया जाना और उसके कारण बाधित होती आर्थिक गतिविधियां और उसके फलस्वरूप सरकार

द्वारा टैक्स प्राप्ति के लक्ष्य प्राप्ति में बाधाएं चिंता का कारण बन रही थी। कीमतों में थोड़ा बहुत उछाल आने से आर्थिक गतिविधियों को वास्तव में प्रोत्साहन मिल सकता है। एक अमरीकी अर्थशास्त्री, एलबॉन फिलिप्स के विश्लेषण को मानें तो मुद्रास्फीति में हुई यह वृद्धि एक अच्छी खबर है क्योंकि इससे आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा, मांग बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा और बेरोजगारी भी घटेगी। इसे समझते हुए कि देश में मांग में धीमापन रोकने की जरूरत है पर इसके लिए राजकोषीय संतुलन को बनाए रखते हुए, आर्थिक गतिविधियों का ऐसे संचालन करना होगा कि अन्य प्रकार से बिगाड़ न हो जाए। गौरतलब है कि वर्ष 2008 में वैश्विक मंदी के बाद यूपीए सरकार ने करों में छूट और सरकारी खर्च में अनाप-शनाप वृद्धि करनी शुरू कर दी थी। उसका परिणाम यह हुआ कि देश का राजकोषीय संतुलन बिगाड़ गया। राजकोषीय घाटा जीडीपी के 6 प्रतिशत से भी ज्यादा बढ़ गया। कीमतों में बेहताशा वृद्धि होने लगी, उसके कारण ब्याज दरों में तेजी से वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप जीडीपी विकास दर धीमी हो गई। विकास दर लगभग 5 प्रतिशत पर और मुद्रास्फीति दो अंकों को पार करते हुए 12 प्रतिशत तक पहुंच गई थी। इसे अर्थशास्त्र में सबसे ज्यादा अवांछनीय स्थिति माना जाता है, जब तेजी से बढ़ती मुद्रास्फीति के स्थान पर जीडीपी में धीमा विकास हो।

वर्तमान सरकार समझदारी के उपाय अपना रही है और उन्हें सराहा भी जा रहा है। हर हालत में राजकोषीय घाटे को एक सीमा से ज्यादा बढ़ने नहीं दिया जा रहा, जिससे ब्याज दरें घटाई जा सकी हैं। इससे उपभोक्ता व निवेश मांग दोनों के बढ़ने की संभावना है। स्थिर पुँजी निर्माण गति में थोड़ी वृद्धि भी हुई है। देश में निवेश वातावरण को बेहतर बनाने के लिए कॉर्पोरेट कर की दर घटाकर 22 फीसदी व नई कंपनियों के लिए मात्र 15 फीसदी किया गया है, जो अन्य कम करों वाले एशियाई देशों के समान है। माना जा रहा है कि सरकार द्वारा दिए जा रहे तमाम प्रोत्साहन दीर्घकाल में न केवल आर्थिक गतिविधियों, उत्पादन और रोजगार बढ़ाएंगे, इससे सरकारी राजस्व भी बढ़ेगा।

— संपादक